भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5139
उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2025

ओडिशा में भारतनेट परियोजना

5139. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर कंधमाल जिले में 4जी/5जी मोबाइल नेटवर्क और भारतनेट फाइबर कनेक्टिविटी के विस्तार में क्या प्रगति हुई है;
(ख) चालू वित्त वर्ष में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत प्रस्तावित नए टावरों और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की संख्या सहित दूरसंचार अवसंरचना को बढ़ाने के लिए सरकार की भविष्य की योजनाएं क्या हैं; और
(ग) कया सरकार के पास जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का विस्तार करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रोत्साहन या विशेष योजनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) ओडिशा में और कंधमाल जिले में 4जी/5जी मोबाइल नेटवर्क और भारतनेट फाइबर कनेक्टिविटी के विस्तार में पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान हुई प्रगति निम्नानुसार है:

मद का नाम	निम्नलिखित तारीख तक	ओडिशा	कंधमाल जिला
4जी/5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या	31.03.2022	52,082	359
	31.03.2023	57,935	409
	31.03.2024	69,920	660
	28.02.2025	74,283	983
भारतनेट परियोजना के तहत सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों की संख्या	31.03.2022	6,672	153
	31.03.2023	6,782	170
	31.03.2024	6,785	171
	28.02.2025	6,785	171

(ख) से (ग) सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित सेवा से वंचित दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से वित्तपोषण के साथ 'भारतनेट' और विभिन्न मोबाइल परियोजनाएं शुरू की हैं। फरवरी-2025 तक की स्थिति के अनुसार; देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,323 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है और 17,341 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने रिंग नेटवर्क पर देश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए, भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और शेष गैर-ग्राम पंचायत गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है।

*****